ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कितने कर्मचारी हैं काम के

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 4 सितम्बर, शिक्षकों के अलावा, आंगनवाड़ी, सहायिका, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, कोटेदार, हैंडपंप मिस्त्री,स्वास्थ्य कर्मचारी, बिजली विभाग और जंगल विभाग के कर्मचारियों का पंचायतों से सम्बंध होता है.

लेकिन सामन्यत: लोग पटवारी और सचिव के अलावा किसी कर्मचारी को नहीं जानते हैं. यही कारण है कि शेष कर्मचारी कभी भी पंचायतों में नहीं जाते हैं और तमाम लोग शासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित रह जाते हैं. जबकि शासन की योजनाओं का बंदरबांट कागजों पर निरंतर होता रहता है. जैसे कृषि विभाग में प्रत्येक वर्ष मुफ्त और रियायती दरों में बीज़ आते हैं लेकिन किसानो को कभी उपलब्ध नहीं होते. लगभग 90% किसान तो ग्राम सेवकों को जानते भी नहीं है. इसी तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर, पानी की गोली मिलनी चाहिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मचारी कभी कभार ही दिखाई देते हैं. आश्चर्य की बात है कि हर पंचायत में एक हैंडपंप मिस्त्री नियुक्त है जिसका वेतन पीएचइ विभाग से मिलता है लेकिन ये बात किसी को भी नहीं मालूम है. क्षेत्र के ग्राम पंचायत में तैनात विभिन्न प्रकार के कर्मचारी का वेतन शासन की ओर से लगभग 50 लख रुपए क्षेत्र में बटता है. किंतु उन पैसे की उपयोगिता ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग शून्य के बराबर ही है. बनवासी विकास परिषद के संयोजक माधव प्रसाद दुबे ने शासन से मांग की है कि ग्रामीण अंचलों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक की जाए तथा उनका वेतनमान भी लोगों के सामने लाया जाए.

पंचायत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी उनका नाम उनका दायित्व और उनका मोबाइल नंबर पंचायत भवन अथवा स्कूल या अन्य जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर प्रदर्शित किया जाए जिससे पता चल सके कर्मचारी को क्या करना चाहिए और कहां पर वे रहते हैं.

पर्यावरण संरक्षण और नियमों की दी गई कार्यशाला में जानकारी

प्रदूषण रोकने के दिये गये सुझाव, पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचता है वैज्ञानिकों ने समझाया

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 सितम्बर, समदड़िया होटल सभागार, रीवा में पर्यावरणीय अधिनियमो पर पारदर्शी एवं प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण संरक्षण एवं मानवाधिकारो के हनन विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय रीवा एवं क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा के संयुक्त तत्वाधान मे आयोजित किया गया.

मुख्य अतिथि के रूप मे अपर जिला न्यायाधीश मोहित कुमार, न्यायाधीश/सचिव समीर कुमार मिश्रा एवं जिला विधिक अधिकारी अभय मिश्रा तथा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के

सेवा निवृत्त डायरेक्टर पर्यावरण पी.के. त्रिवेदी विषय विशेषज्ञ, क्षेत्रीय अधिकारी, एस.पी. झा., बोर्ड उपस्थित रहे. कार्यशाला में उदबोधन देते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, एस.पी. झा द्वारा नियमो अधिनियमो के संबंध मे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई. तदोपरांत लोक अभियोजक अभय मिश्रा द्वारा पर्यावरण की वर्तमान मे मानव द्वारा की जा रही क्षति को रोकने के लिए जन अभियान चलाये जाने पर जोर दिया, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे.

समीर मिश्रा न्यायाधीश/सचिव द्वारा पर्यावरणीय नियमो को अधिक-अधिक से जन सामान्य को समझाने एवं उसका उपयोग पर्यावरण के संरक्षण हेतु की जाने वाली कार्यवाही को संक्षम एवं प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित करने हेतु सभी संबंधित विभागो को जन अभियान के रूप मे चलाये जाने का आवांहन किया गया साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान एवं कोलाहल अधिनियम 2000 के बारे मे विस्तृत रूप से अवगत कराया गया. मुख्य अतिथि की आसंदी से अपर जिला न्यायधीश मोहित कुमार द्वारा वातानुकूलित संयंत्रो से होने वाले कार्बन उर्त्सजन, ग्रीन हाउस गैसो के उत्सर्जन से ओजोन परत को होने वाली क्षति एवं बढ़ते तापक्रम के संबंध मे विस्तृत उद्बोधन दिया गया. इसी तारतम्य मे बोर्ड अधिवक्ता रोजेन्द्र तिवारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय रीवा क्षेत्रान्तर्गत जल/वायु अधिनियमो के तहत वाद दायर किये गये है उनके संबंध मे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई. कार्यशाला मे विषय विशेषज्ञ के रूप मे उपस्थित हुए म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के सेवा निवृत्त डायरेक्टर पर्यावरण पी.के. त्रिवेदी द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा इसके अन्तर्गत आने वाले समस्त नियमो के बारे मे विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया. कार्यालय का संचालन डॉ. अशोक तिवारी, वैज्ञानिक द्वारा किया गया. इस अवसर पर के एम.पी. तिवारी, सहायक यंत्री, डॉ. संजय मिश्रा, वैज्ञानिक, डॉ शुभी माथुर, वैज्ञानिक, रामनारायण चतुर्वेदी मौजूद रहे.

खाद की भीषण समस्या से किसान परेशान है : ज्योतिनारायण

नवभारत न्यूज

गुढ़, 4 सितम्बर, भारतीय सर्व सेवा संगठन के जिला अधक्ष मऊगंज किसान ज्योति नारायण पिड़िहा ने कहा कि किसान खाद के लिये परेशान है.

आज सिरमौर क्षेत्र के उमरी मोड में खाद की समस्या को लेकर उमरी मोड चौराहे में चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई है. बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है जिस तरह से किसान खाद के लिए परेशान हैं काफी चिंताजनक है. सरकार तो

गहरी नींद में सोई हुई है. क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी किसानों की समस्या पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की सरकार होने का दावा किया जाता है. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है किसानों के मुद्दे पर किसी भी सत्ताधारी दल का नेता सामने अब तक नहीं आए हैं.

किसान नेता ज्योति नारायण पिड़िहा ने जिला प्रशासन से किसानों को शीघ्र खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है.

वासुदेव भुर्तिया का निधन

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 4 सितम्बर, नगर की सीमा से लगे शिव जियावान इंटर कॉलेज लेडियारी के ऊप प्रबंधक वासुदेव भूर्तिया का 85 वर्ष की आयु में गत दिवस निधन हो गया.

वे चाकघाट के निकट त्योंथर अंचल के ग्राम कुडरी के मूल निवासी थे. वे एक अच्छे कृषक के साथ सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हुए विद्यालय प्रबंधन से जुड़े रहे. निधन पर डॉ बी.एल भुर्तिया, अभिमन्यु भुर्तिया, राम कैलाश भुर्तिया, पूर्व सरपंच विजय शंकर, पूर्व बैंक प्रबंधक मोहनलाल गुप्ता, साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार राम लखन गुप्ता आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की है.

मऊगंज में डीईओ कार्यालय स्थापित हो : प्रान्ताध्यक्ष

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 4 सितम्बर, सर्व शिक्षक संघ मऊगंज के प्रान्ताध्यक्ष सतानन्द मिश्र ने मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन से मांग की है कि नवीन जिलों मऊगंज, मैहर, एवं पाण्दुर्ना में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना की जाय.

स्कूल शिक्षा विभाग भारी भरकम अमला वाला विभाग है. गांव-गांव में स्कूले हैं किन्तु जिला मुख्यालय में कार्यालय नहीं है जिससे अराजकता एवं घूंसखोरी, दलाली बढ़ रही है. संकुल बी0. ई0 ओ0, डी0 ई0 ओ0, डी0 पी0 सी0 पेंशन सभी कार्यालयों में लेन-देन अराजकता का महौल बना दिया गया है जिससे शिक्षकों के स्वत्वों का निराकरण समय समय पर समान रूप् से नहीं हो रहा है. सभी काम प्रभावित हो रहे है.

हनुमना के मोरहना गांव में बनेगी 130 एकड़ में गौशाला

नवभारत न्यूज

हनुमना, 4 सितम्बर, लंबे समय से आवारा पशुओं की समस्या को लेकर उठ रही आवाज़ आखिरकार रंग लाई.

उल्लेखनीय है कि मऊगंज कलेक्टर ने हनुमना तहसील के मोरहना गांव में 130 एकड़ जमीन स्वावलंबी गौशाला हेतु आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं. यह निर्णय क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. गौरतलब है कि सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही थीं. भले ही 1 सितंबर को सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव पारित किया गया हो लेकिन उसी दिन पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी इस गंभीर समस्या को प्रशासन के सामने मजबूती से रखा, जिसके बाद ही कलेक्टर कार्यालय से उपरोक्त पारित आदेश की प्रति उसी दिन शाम को तत्काल प्रभाव से जमीन आवंटन का आदेश जारी किया जाना सिद्ध करता है कि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की आवारा पशुओं को मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए जैसी चेतावनी के भय का भी कही न कही असर पड़ा है. दूसरी ओर ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही गौशाला का निर्माण कार्य शुरू होगा. जिससे सड़कों पर आवारा पशुओं का आवागमन कम होगा और किसानों को भी बड़ी राहत मिलने के साथ आए दिन होने वाली आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं एवं दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने के साथ ही गोवंश को भी सड़क दुर्घटनाओं में बचाए जा सकेगा. किसानो ने भी राहत की सांस ली.

मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए छात्र

नगर परिषद कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है हर माह वेतन

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 4 सितम्बर, इस समय त्योंथर क्षेत्र की दो नगर परिषद् त्योंथर एवं चाकघाट कंगाली के कगार पर पहुंच रही हैं.

जिसके चलते यहां कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिमाह निर्धारित समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही नगर परिषद के द्वारा जनहित में छोटे-मोटे कार्य कराए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में नगर परिषद को मध्य प्रदेश शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती थी जिस राशि से नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था किंतु इधर लंबे समय से शासन द्वारा दिए जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से विद्युत बिलों के भुगतान एवं नगर परिषद द्वारा विकास कार्यों के लिए के लिए दिए गए कर्ज की किस्त ऊपर से ही काट कर शेष राशि नगर परिषद को में भेजी जा रही है.

कटौती के पश्चात यह राशि इतनी कम हो जाती है कि कर्मचारियों का वेतन मिल पाना मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं पैसे के अभाव में कुछ स्थानों पर कर्मचारियों के वेतन से कटौती करके जो राशि भविष्य निधि खाते में जमा होनी चाहिए वह राशि भी लंबे समय से उनके खाते में जमा नहीं हो पा रही है,

जबकि वेतन से वह राशि काट ली जा रही है. नगर परिषद में आए दिन कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपने कुछ चहेतों को कार्यालयीन कार्य एवं व्यवस्था के नाम पर रख लिया जाता है और बाद में इनकी संख्या हर 5 वर्ष में नए अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ ही बढ़ती जाती है जिनको दिए जाने वाला वेतन का भार भी नगर परिषद को पड़ता है.

मध्य प्रदेश शासन से आग्रह है कि आर्थिक मामलों में बदहल हो रहे नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन हेतु कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाय.

चयन परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान

नवभारत न्यूज

हनुमना, 4 सितम्बर, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2022 में जारी किया गया था.

जिसकी पात्रता परीक्षा माह अप्रैल 2023 में आयोजित की गई तथा चयन परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2025 में किया गया. चयन परीक्षा को संपन्न हुए लगभग 4 माह का समय बीत चुका है. लेकिन आज दिनांक तक चयन परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है. उक्त विलंब के कारण लाखों अभ्यर्थी मानसिक रूप से अत्यंत तनाव चिंता एवं असमंजस की स्थिति में है इस अनिश्चितता के कारण कई अभ्यर्थियों का मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है और वह आर्थिक व पारिवारिक दबाव का भी सामना कर रहे हैं मान्यवर शिक्षक भर्ती जैसे अति महत्वपूर्ण विषय में इस प्रकार की देरी न केवल उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित करती है. अपितु शिक्षा व्यवस्था में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को भी बाधित करती है इन सभी अभ्यर्थी मांग करते हैं कि आप इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में ले तथा विभाग संबंधित विभाग को निर्देशित करें कि तुरंत अभ्यार्थियों परीक्षा परिणाम जारी किया जाए धैर्य की भी सीमा होती है. ज्ञापन के पश्चात भी कोई ठोस कार्रवाई या सृष्टीकरण विभाग की तरफ से जारी नहीं होता है तो हमें मजबूरन संबंधित विभाग लोक शिक्षण न्यायालय तथा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के सामने प्रदर्शन करना होगा. जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी. इस दौरान मऊगंज में भी जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देने में मुख्य रूप से अजय तिवारी सज्जन तिवारी रिंकू प्रजापति रोहित तिवारी प्रभात द्विवेदी द्वारा जिला कलेक्टर मऊगंज को ज्ञापन सौपा गया.

नईगढ़ी क्षेत्र की अराजकता विभिन्न मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन देने की तैयारी

नवभारत न्यूज

नईगढ़ी, 4 सितम्बर, प्रदेश के मुखिया डा0 मोहन यादव 7 सितम्बर को मऊगंज जिले के देवतालाब आ रहे है, जहा विभिन्न कार्यक्रमो में शामिल होगे. वही नईगढ़ी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओ और थाना प्रभारी की मनमानी को लेकर ज्ञापन सौपने की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौप कर कार्यवाही की मांग की जायेगी.

मऊगंज जिले के नईगढ़ी क्षेत्र में खुलेआम मादक पदार्थ अवैध तरीके से बिक रहे है, यहा अराजकता का माहौल है. कई मीडिया कर्मियो पर प्रकरण दर्ज किया गया. अव्यवस्था और ड़र का वातावरण क्षेत्र में बना हुआ है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जायेगी. अगस्त क्रांति मंच एवं व्यापारी मजदूर सहित विभिन्न संगठन की समस्याओ का ज्ञापन सौपने की तैयारी में है. अलग-अलग बिंदुओ के साथ ज्ञापन पत्र तैयार किया गया है जिसमें कई गंभीर समस्याओ का उल्लेख करते हुए कुछ मांगे भी रखी जायेगी. मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपने के पहले ही क्षेत्र में ज्ञापन की कापी बट गई है. जिसे मुख्यमंत्री के आगमन पर सौप कर निराकरण की मांग की जायेगी. ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कर आम जनता, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया जा रहा है, मुकदमा वापस किया जाय. इसी तरह गांव-गांव गली-गली खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, जिसमें शराब, गांजा, अफीम और अन्य मादक पदार्थ आसानी से बिक रहे है, जिस पर रोक लागई जाय. किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं, ऊपर से बिजली बिल की मार झेल रहे हैं. मनमानी पर बिल पर रोक लगे. निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है. राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों और अराजक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है. पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीने जा रहे हैं. जल जीवन मिशन घोटाले में जनता को एक बूंद पानी नहीं मिला, केवल फर्जी सील और हस्ताक्षरों से कागजों पर पूर्णता प्रमाण पत्र बना दिए गए. जिसकी जांच कराई जाय. शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर हो चुकी है उसे बेहतर बनाया जाय. दर्जन भर से अधिक मांगे शामिल की गई है. अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंजबिहारी तिवारी पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी द्वारा यह मांग पत्र सौपकर कार्यवाही की मांग की जायेगी.

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव

रीवा, 4 सितम्बर, कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य के तौर पर वनमण्डलाधिकारी, बवोल प्रसाद कोल, श्रीमती अनीता सिंह एवं श्रीमती बूटी कोल को शामिल किया गया है. समिति के सदस्य सचिव जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग होंगे.

दिल्ली में होगा 13 व 14 को हिंदी सम्मेलन व राष्ट्रभाषा अभिव्यक्ति सभा

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 4 सितम्बर, प्रेरणा हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान के तहत आगामी 13 सितंबर को हिंदी सम्मेलन व 14 सितंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु अभिव्यक्ति सभा आयोजित किया जा रहा है.

प्रेरणा हिंदी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कवि संगम त्रिपाठी ने एक जानकारी में बताया है कि आयोजित कार्यक्रम में भारत देश के विभिन्न प्रांतों के साहित्यकार पत्रकार कवि कवयित्री भाग लेंगें. इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी हिंदी प्रेमियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

दो दिवसीय इस आयोजन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अभिव्यक्ति के साथ ही कविता पाठ व हिंदी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए लोगों को सम्मानित किया जाएगा. प्रेरणा हिंदी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कवि संगम त्रिपाठी ने हिंदी साहित्यकारों लेखकों एवं पत्रकारों से अपील है कि कार्यक्रम में भाग लें.

सेंटर लाइन में लगाए जाने वाला चेक प्वाइंट जानलेवा सिद्ध हो रहा है

नवभारत न्यूज

हनुमना, 4 सितम्बर, हनुमना बॉर्डर पर आरटीओ विभाग द्वारा सेंटर लाइन में लगाए जाने वाला चेकप्वाइंट मौत का पॉइंट बन चुका है.

कई ऐसी घटनाएं घटने के बाद भी आरटीओ विभाग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और सेंटर लाइन पर ही चेक पॉइंट लगाकर चैकिंग करता है इसी सेंटर पॉइंट से क्योंकि आम लोगों का एवं आम वाहनों का भी आना-जाना बना रहता है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना सदैव बनी रहती है पूर्व में मिर्जापुर जिले के एक युवक की जान इसी केंद्र बिंदु पर निकल रहे ट्रक से बचने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर हो गई थी वही दो दो चक्कर आरटीओ विभाग के ही दो कर्मचारी ट्रक के चक्के के नीचे आकर मरते मरते बच गए. दो माह पूर्व ही हनुमना नगर केही राजू गुप्ता तथा केशव सोनी नामक युवकों को इसी सेंटर लाइन पर लगाए जाने वाले चेक पॉइंट के चलते ट्रक की चपेट में आने से गंभीर चोटें आई थी इतना ही नहीं यह तो संयोग था कि उपस्थित सारे लोगों ने इतनी तेज हल्ला किया कि ट्रक वाला घबराकर गाड़ी बंद कर दिया नहीं तो वह हाईवा ट्रक के नीचे आकर इस कदर चके के नीचे था कि दो अंगुल भी ट्रक बढ़ता तो सर चकनाचूर हो जाता। ढलान ज्यादा होने एवं सड़क की चौड़ाई भी कम होने से वहां चेकिंग लगाना खतरे से खाली नहीं है लेकिन बावजूद इसके आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी सेंटर लाइन पर ही अक्सर चेकिंग लगाते हैं जबकि पूर्व में आरटीओ चेक पोस्ट जहां बना हुआ है वहां 6 लाइन होने के साथ काफी स्पेस और समतल होने से खतरे से निजात मिल सकती है.

हनुमना नगर की बेटी का पुलिस में चयन

नवभारत न्यूज

हनुमना, 4 सितम्बर, वार्ड क्रमांक 10 निवासी धनंजय गुप्ता की पुत्री प्राजंलि गुप्ता का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हुआ है. इस सफलता के बाद पूरे परिवार और समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है.

समाज के लोगों का कहना है कि प्राजंलि गुप्ता ने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी. वही मगर व क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों व परिजनों ने बधाई देते हुए प्रांजलि के उज्जवल भविष्य की कामना की है. बधाई देने वालों में से विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी प्रख्यात नाड़ी विशेषज्ञ सरयू प्रसाद वैद्य, वरिष्ठ समाजसेवी दीनानाथ गुप्त, नगर परिषद अध्यक्ष सोनू आशुतोष गुप्ता नगर परिषद उपाध्यक्ष शरद जय गुप्ता वार्ड पार्षद नवनीता तारकेश्वर गुप्ता, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष क्रमश: शैलजा गुप्ता पूनम गुप्ता रमेश जायसवाल सुशीला गुप्ता अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल और केसरी शैलेंद्र गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार संपत्ति दासगुप्त सरोज गुप्ता श्याम बाबू गुप्ता टिंकल केसरी मनोज कुमार गुप्त आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी.

जिला विकास संघर्ष परिषद् ने विधायक को सौंपा मांग पत्र

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 4 सितम्बर, आगामी 7 सितम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मऊगंज जिले के दौरा कार्यक्रम के तहत जिला विकास संघर्ष परिषद् मऊगंज के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम के आयोजक विधायक देवतालाब गिरीश गौतम को मऊगंज जिले के जनहित के मुद्दों को मांगपत्र में शामिल किये जाने की मांग की.

विधायक गिरीश गौतम के भ्रमण कार्यक्रम के तहत बरहटा रोड मऊगंज में मांगपत्र सौंपा गया. जिसमें मऊगंज जिले को रेल सेवा से जोड़ने, मऊगंज में प्रधान जिला व सत्र न्यायालय की स्थापना, मऊगंज जिले में जिला प्रमुखों के कार्यालय

के तहत प्रथम चरण में स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, जिला पंचायत, पी0 एच0 ई0 व जिला कोषालय (ट्रेजरी) के कार्यालय संचालित किये जाने मऊगंज जिले में व्याप्त बेराजगारों व मजदूरों की पलायन की विभीषिका के लिये उद्योग समूहों की स्थापना, जिले के अधीन देवतालाब विधानसभा में मौजूद ओड्डा नदी के गहरीकरण व चैंड़ीकरण कराकर किसानों के हित के साथ प्राचीन बहुती प्रपात के गौरव व छटा को विद्यमान रहने की व्यवस्था, जिला मुख्यालय में स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष स्थित बरांव चैराहे पर ओवर ब्रिज के निर्माण, जिले के किसानों के कल्याण व उत्थान हेतु केन्द्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, मऊगंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय का संचालन सहित कई मांग शामिल है.

मांग पत्र सौंपने में जिला विकास संघर्ष परिषद् के संयोजक अधिवक्ता संतोष मिश्रा, वरिष्ठ सदस्य कर्दम ऋषि, पं. केशव प्रसाद मिश्र घुरेहटा, यज्ञनारायण द्विवेदी, विद्याधर मिश्र शामिल थे.